Shri D. C. Shrama: The hon. Minister has not given a reply to my question whether it would be in the Third Five Year Plan or in the Fourth Five Year Plan.

Sardar Swaran Singh: I have already stated that the final decision can be taken only after commercial tests are undertaken. Commercial tests will be undertaken after the lignite is available; that is after September. Depending on the results of that, the final decision can be taken. So, it is premature for me to say whether there will be a steel plant or not; much less to say whether it will be in the Third Plan or in the Fourth Plan.

Shri C. R. Pattabhi Raman: Will the railway line from Neyveli to Salem—and other transport routes also—be taken along with this or will they have to wait for investigation?

Sardar Swaran Singh: It is a suggestion for action, Sir.

श्रीमती कृष्णा मेहता : क्या जम्मू कश्मीर रयासत में भी कोई इस्पात कारखाना खोलने का विचार है क्योंकि जम्मू के इलाके में भाला कोट में कोयला वगैरह बहुत पाया जाता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अगर कच्चा माल वहां ज्यादा होगा तो उस पर भी विचार किया जा सकता है ।

Shri Narasimhan: For the purposes of test only a comparatively small quantity of lignite is needed. Why should so many months be neded for getting out this small quantity of lignite?

Mr. Speaker: We are going into details.

Shri Narasimhan: Sir, the reason given was that it was pending for the collection of the necessary quantity of lignite. But, I want to know why there should be such a difficulty for getting a small quantity of lignite. Upward thrust of water need not stand in the way of getting a small quantity?

Sardar Swaran Singh: The quantity needed is not small. Secondly, even for mining a small quantity the upward thrust of water cannot be ignored.

Mr. Speaker: The other day the same question were put and the answer was that some ten thousand tons have to be exported.

Shri Tangamani: One thousand tons.

Mr. Speaker: It was said that 1,000 tons were necessary. The hon. Minister said that he wanted to find out whether it can be done on a commercial basis. Hon. Members are present on some days and not present on other days. So, they put the same questions again and again.

Coal and Steel for Punjab

\+

*1748. **Shri Ram Shankar Lal:**
Shri Ajit Singh Sarhadi:
Shri Daljit Singh:
Shri Shri D. C. Sharma:
Shri Hem Raj:
Shri Pangarkar:

Will the Minister of **Steel, Mines and Fuel** be pleased to state:

(a) whether the Punjab State Government have requested that the quota of coal and steel for the small scale industries be increased for 1961;

(b) if so, the quantity of coal and steel demanded;

(c) the decision taken by the Government of India; and

(d) whether the Government of India contemplates increase because of lack of heavy industries in Punjab?

The Minister of Steel, Mines and Fuel (Sardar Swaran Singh) (a) to (d). The Punjab Government have not actually asked for an increased quota of steel and coal for the small

scale industries for 1961, but they have pressed for larger supplies against the existing allocations, as actual supplies have not been to the full extent of the quotas. Steps have been aken to increase the supplies of steel by giving priority to one third of the allocations made to small scale industries and by arranging more supplies from imports; in respect of coal movement will be effected in block rakes and this is expected to improve supplies. It is proposed to meet the requirements of hard coke for foundries and engineering concerns in the Punjab to the full extent of their quota.

Shri D. C. Sharma: Has the hon. Minister read the speech of the hon. Chief Minister of Punjab State in Delhi in which he has complained that the industries in Punjab are not functioning properly because of the shortage of coal and steel? If it is so, may I know how much of additional coal and steel has been asked for by the Punjab Government and how much has been supplied?

Sardar Swaran Singh: I have covered all these in my reply. The quotas are already there. Movement of supplies has not been in accordance with those quotas. Steps are now being taken to step up the supply against allocations.

Shri D. C. Sharma: The hon. Minister has given a very involved reply and I want a clarification of it. May I know how much of coal quota has been allotted, how much of that quota has been moved so far; how much of steel quota has been allotted and how much of that quota has been moved so far? What are the arrangements made for the movement of the quotas? I want a clarification.

Sardar Swaran Singh: An involved question can be answered only by an involved reply. The best thing would be for the hon. Member to put a separate question. About the quota I have no information at the moment.

390(Ai)LSD—2.

Shri Ram Krishan Gupta: May I know whether the number of iron and steel stockists is sufficient to meet the demand for this purpose?

Sardar Swaran Singh: I do not think the shortage of the number of stockists has been a matter about which any complaint has been received.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जब सरकार की नीति छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने की है, और पंजाब में छोटे उद्योगों की बहुतायत है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो कोयला और इस्पात आप ने उन को दिया है वह क्या बहुत थोड़ा नहीं है ? और इस को भविष्य में बढ़ाने के लिये आप ने क्या निश्चय किया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यही तो मैं ने अपने जवाब में कहा है कि उस के बढ़ाने का यत्न किया जा रहा है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि इन फैक्ट्रियों में जो छोटे उद्योग चल रहे हैं उन को देखते हुए आप ने कितने प्रतिशत बढ़ाने का निश्चय किया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : बढ़ाने का सवाल नहीं है क्योंकि शिकायत कोटा कम होने के मुताल्लिक नहीं है । जितना कोटा उन को दिया गया था उस कदर माल उन को नहीं पहुंच पाया है, यह शिकायत है, और उस के मुताल्लिक मैं ने अपने जवाब में जो जो लेटेस्ट पोजीशन है उस का जिक्र किया है ।

श्री अजराज सिंह : जुलाई के बाद जो कोयले के २०० वैगन प्रति दिन के हिसाब से मोगलसराय के उत्तरी हिस्से में अधिक आयेंगे उन में से कितने सरकार पंजाब के लिये देने को तैयार है, और क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन से आधार हैं जिन के अनुसार विभिन्न स्थानों में, विभिन्न राज्यों में

स्टील और कोयले के कोटे निश्चित किये जाते हैं, या सिर्फ प्रान्तीय सरकारों की सिफारिश पर ही विचार किया जाता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जो २०० कोयले के डब्बे जुलाई के बाद मोगलसराय से ऊपर जाने वाले हैं उन के मुताल्लिक अभी निश्चय नहीं किया गया कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात या शुमाली हिस्से, में महाराष्ट्र वगैरह किस हिस्से में कितना कोयला और जायेगा । जो दूसरा सवाल माननीय मेम्बर ने पूछा है उस के मुताल्लिक प्रान्तीय सरकारों की सिफारिश भी ली जाती हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज हैं उन के मुताल्लिक सेंटर की इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की सिफारिशात का भी ख्याल रक्खा जाता है ।

जिला सैनिक, नौसनिक और वायु बोर्ड

*१७४६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में जो जिला सैनिक, नौसैनिक व वायु बोर्ड कई वर्षों से अस्थायी रूप से कार्य करते आ रहे हैं, उनके स्थायीकरण के प्रश्न पर कुछ समय से विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ; और

(ग) वह निश्चय कब से लागू किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन । मामला बहुत दिनों से विचाराधीन रहा है और पिछले साल इस बारे में जो बड़ी भारी कांफरेंस की गई थी उस में भी इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था । तो इस बारे में इतनी देरी होने का क्या कारण है ?

सरदार मजीठिया : चूंकि इन बोर्डों को चलाने के लिये ५० फी सदी रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है और ५० फी सदी स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है इसलिये इस मामले को तय करने में जितनी देरी स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ सहमत नहीं होती उतनी देर तक इस का फैसला नहीं किया जा सकता ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन । क्या गवर्नमेंट को इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि प्रायः दो वर्षों से कई कई महीनों तक इन कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिलता, और इस गड़बड़ी का कारण यह है कि उन को अभी तक परमानेन्ट नहीं किया गया है ? तो क्या गवर्नमेंट इस बारे में शीघ्रता करेगी और उन के वेतन की अदायगी नियमित रूप से की जायेगी ?

सरदार मजीठिया : जी हां, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ सहमत हो जायें ताकि हम इस मामले में आगे बढ़ सकें ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन । राज्य सरकारों से अब तक जो पत्र व्यवहार किया गया है उस के फलस्वरूप क्या राज्य सरकारों ने कोई राय दी है ? जहां तक मुझे मालूम है वे इस से सहमत हैं ।

सरदार मजीठिया : कोई आधी सरकारों ने राय दी हैं । वे आधी सरकारें सहमत हैं । लेकिन दूसरी आधी सरकारों के जवाब नहीं आये हैं । हम उन का इन्तजार कर रहे हैं ।